कब मिलेगा बिहार को आई.आई.एससी. आर.ई.

बिहार प्रदेश को केन्द्र सरकार के शैक्षणिक बजट (विज्ञान और तकनीक के लिए) का बहुत कम हिस्सा मिलता है। पिछले कई वित्तीय वर्षों के केन्द्रीय बजट के अध्ययन से पता चलता है कि भारत सरकार जहां प्रतिव्यक्ति दिल्ली में उच्च शिक्षा पर 100 रु. खर्च करी है, वहीं उत्तरांचल में 59.51 रु., अरुणाचल प्रदेश में 43.86 रु., असम में 19.07 रु., प. बंगाल में 14.18 रु., कर्नाटक में 10.00 रु., झारखंड में 9.06 रु., महाराख्ट्र में 9.64 रु. और बिहार में 105 रु.।

डा. राजकिशोर प्रसाद

बिहार विकसित भारत का एक विकसित राज्य होना चाहता है। बिहार को विकासशील बनाने के लिए काफी चीजों की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं है कि बिहार कुछ खास क्षेत्रों में आगे है और शेष क्षेत्रों में विकास करना बाकी है। विकास का लाभ सभी क्षेत्रों में करना है और संसाधन सीमित है। यही कारण है कि बिहार का विकास एक कठिन समस्या है और इसके लिए कई दीर्घकालिक और दूरदर्शी योजनाओं के साथ चलने की जरूरत है, जिसमें सत्ता परिवर्तन होने से भी बहुत कुछ बदलाव और रुकावट न लाया जा सके। किसी राज्य या देश को विकसित बनाने में वहां की शैक्षणिक व्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। बिहार के विकास के लिए भी यह अतिआवश्यक है कि यहां के शैक्षणिक संस्थानों का कायाकल्प हो तथा कुछ उम्दा स्तर की नवीन शोध एवं शैक्षणिक संस्थाएं खोली जाएं, जो आज के विश्वव्यापी दौर में उन्नत शिक्षा दे सकें और शोध के क्षेत्र में बिहार में एक नये आयाम की शुरुआत कर सकें। विज्ञान और तकनीक के इस दौर में इन दोनों क्षेत्रों में उन्नति के बगैर अन्य क्षेत्रों में सार्थक उन्नति संभव नहीं है। अतएव, बिहार को इन दोनों क्षेत्रों में शिक्षा और शोध की उन्नत कोटि के संस्थानों की अविलम्ब जरूरत है।

कुछ वर्ष पहले बिहार के पटना अभियंत्रण महाविद्यालय, पटना को एन.आई.टी. का दर्जा दिया गया। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि एन.आई.टी. पटना अगले कुछ वर्षों में अभियंत्रण व तकनीक के क्षेत्र में एक उन्नत दर्जे के पाठन व शोध संस्थान के रूप में स्थापित हो जाएगा। अभी बिहार में उच्च दर्जे का एक भी संस्थान नहीं है जो विज्ञान के पाठन व शोध में बिहार को एक नई दिशा दे सके। वैसे तो पूरे देश में विज्ञान के पाठन व उच्च स्तरीय शोध संस्थान की कमी रही है। दिसम्बर, 2003 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति महोदय ने देश में राष्ट्रीय विज्ञान शोध संस्थान (एन.आई.एस.सी.) खोलने के आवश्यकता पर ध्यान दिलाया था।

डा. राजवि
शोर प्रसाद

उसी अवसर पर बोलते हुए पूर्व मानव संसाधन मंत्री डा. मुरली मनोहर जोशी जी ने भी इस पर सहमति जताई थी। तदुपरांत यू.जी.सी. ने 10वीं योजना में (पिछले एनडीए सरकार के कार्यकाल में ही) इसी कमी को पूरा करने के उद्देश्य से देश में भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलोर की तर्ज पर चार अन्य राष्ट्रीय विज्ञान शोध संस्थान खोलने की घोषणा की थी जिसके तहत पश्चिम में पूना, पूरब में उत्कल विश्वविद्यालय उड़ीसा, उत्तर में इलाहाबाद तथा द. में चेन्नई को एक एक एन.आई.एस.सी. दिया गया। इन स्थानों में से कहीं भी अबतक राष्ट्रीय विज्ञान शोध संस्थान नहीं खुल पाया। इसी बीच केन्द्रीय सरकार भी बदल गयी। उसे भारतीय राजनीति की खूबी या कमी कहें कि सरकार बदलते ही राष्ट्रीय महत्व के निर्णय भी बदल जाते हैं जिसका प्रभाव विकास कार्यों पर पड़ता है। वर्तमान केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय विज्ञान शोध संस्थान के मुद्दे पर चुप है मगर देश में 500 करोड़ रुपये की लागत से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सायंस फॉर रिसर्च एंड एडुकेशन (आई.आई.एससी.आर.ई.) यानी राष्ट्रीय विज्ञान शोध एवं शिक्षक संस्थान खोलने की घोषणा की है और अभी तक कलकत्ता, पुणे, चंडीगढ़ एवं कानपुर में खोला गया जिसमें कोलकाता तथा पुणे में प्रथम सत्र में नामांकन की सूचना भी जारी कर दी गयी है। वर्तमान केन्द्रीय सरकार से जिन राज्यों को आई.आई.एस.सी. आर.ई. पाने का नसीब मिला उनमें दुर्भाग्यवश बिहार अबतक नहीं आ पाया है। बिहार में राष्ट्रीय स्तर का एक भी ऐसा संस्थान नहीं है जहां विज्ञान संकाय में उच्च शिक्षा व शोध के अवसर हों। राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों की कमी के कारण बिहार प्रदेश को केन्द्र सरकार के शैक्षणिक बजट (विज्ञान और तकनीक के लिए) का बहुत कम हिस्सा मिलता है। पिछले कई वित्तीय वर्षों के केन्द्रीय बजट के अध्ययन से पता चलता है कि भारत सरकार जहां प्रतिव्यक्ति दिल्ली में उच्च शिक्षा पर 100 रु. खर्च करती है, वहीं उत्तरांचल में 59.51 रु., अरुणाचल प्रदेश में 43.86 रु., असम में 19.07 रु., प. बंगाल में 14.18 रु., कर्नाटक में 10.00 रु., झारखंड में 9.06 रु.,महाराष्ट्र में 9.64 रु. और बिहार में .05 रु.।

उच्च शिक्षा पर केन्द्र सरकार के खर्च में इतनी क्षेत्रीय विषमता देश के विकास के लिए कतई अच्छे संकेत नहीं कहे जा सकते हैं। शायद प्रधानमंत्री ने अगर क्षेत्रीय असंतुलन को ध्यान में रखा होता तो जरूर इसे बिहार को दे दिया जाता। कई लोग ऐसा तर्क देते हैं कि राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में नामांकन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर होती है इसलिए ऐसे संस्थान बिहार में हों या बाहर क्या फर्क पड़ता है। पर वे यह कहना भूल जाते हैं कि ऐसे संस्थानों के स्थानीय फायदे भी काफी महत्वपूर्ण हैं जिससे बिहार वंचित रह जाता है।

उच्च स्तरीय शोध एवं शिक्षण संस्थान स्थानीय लोगों में उच्च शिक्षा के प्रति जागरुकता लाते हैं। ये संस्थान स्थानीय विश्वविद्यालयों के लिये प्रेरणास्रोत होते हैं तथा उनकी शोध और शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। हमारे यहां ऐसे उच्च स्तरीय शोध संस्थान नहीं हैं जिस कारण स्थानीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के अधिकांश शिक्षक शोध कार्य, उन्मुखीकरण, शोध प्रशिक्षण, सेमिनार, क्यू.आई.पी. आदि से वंचित रह जाते हैं। नये-नये आविष्कारों की बारीक जानकारियां, नवीन शोध पत्र पाठन आदि अतिमहत्वपूर्ण पहलुओं से दरकिनार हो जाते हैं और बच जाती है सिर्फ 'चाक-टाक-रोट-रुटीन' की पढ़ाई जो कि विज्ञान विषय के उच्च स्तरीय पाठन के लिए पर्याप्त नहीं है।

इन सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए बिहार में एक आई.आई.एससी.आर.ई. जैसी संस्था का खुलना अति अनिवार्य लगता है परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि अबतक इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

(लेखक टोकियो, जापान में रिसर्च फेलो हैं।)

From Hindustan, Patna Edition, Dated 01-06-06